एचपीवी टीकाकरण अभियान हुआ प्रारंभ

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भोपाल से किया अभियान का शुभारंभ

भोपाल, 28 फरवरी. मप्र में डॉ. कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल भोपाल से अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने किया. उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक है.

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है, जिसकी प्रिवेलेंस दर लगभग 1 लाख में 156 है. एचपीवी वैक्सीनेशन भविष्य में सर्वाइकल कैंसर को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बीमारी होने के बाद इलाज करने से बेहतर है कि हम उसे होने ही न दें. यह अभियान प्रिवेंशन केयर की दिशा में एक बड़ा कदम है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर मुक्त मप्र और स्वस्थ, आत्मनिर्भर नई पीढ़ी का निर्माण सरकार का संकल्प है.

प्रदेश के 16 जिलों में मिशन मधुहारी भी शुरू

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मिशन मधुहारी का शुभारंभ भी किया. मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में साप्ताहिक विशेष टाइप-1 डायबिटीज क्लिनिक प्रारंभ किए जा रहे हैं, जहां इंसुलिन की सतत उपलब्धता, ब्लड ग्लूकोज जांच, विशेषज्ञ परामर्श एवं नियमित फॉलो-अप की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी. इस अवसर पर 5 बेटियों को टाइप-1 डायबिटीज जांच किट का वितरण भी किया गया. इन किटों में ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि बच्चे समय पर शुगर की जांच कर सकें और बीमारी को नियंत्रित रख सकें.

> **प्रतिदिन होंगे टीकाकरण सत्र**
>
> एचपीवी टीकाकरण सत्र प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किए जाएंगे. टीकाकरण स्वैच्छिक है तथा अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी. पात्रता के तहत वे बालिकाएं शामिल हैं, जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन पूरा कर लिया है लेकिन 15वां नहीं मनाया है, साथ ही अभियान प्रारंभ होने के 90 दिनों के भीतर 15 वर्ष पूर्ण करने वाली बालिकाएं भी पात्र होंगी. समस्त जिलों के लगभग 471 स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण किया जायेगा.

रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर (सेण्ट्रल) रूल्स 1956 के अंतर्गत 'नवभारत' पत्र के संबंध में स्वामित्व तथा अन्य विवरण विषयक जानकारी

घोषणा

(फार्म-4)

1. प्रकाशन स्थल	:	गुजराती समाज भवन, नई आबादी छिंदवाड़ा
2. प्रकाशन रूप	:	दैनिक
3. मुद्रक	:	आशीष श्रोती
नागरिकता	:	भारतीय
निवास स्थान	:	गुजराती समाज भवन, नई आबादी छिंदवाड़ा
4. प्रकाशक	:	आशीष श्रोती
नागरिकता	:	भारतीय
निवास स्थान	:	गुजराती समाज भवन, नई आबादी छिंदवाड़ा
5. संपादक	:	क्रांति चतुर्वेदी
नागरिकता	:	भारतीय
निवास स्थान	:	गुजराती समाज भवन, नई आबादी छिंदवाड़ा
6. पत्र का स्वामित्व भागीदार	:	रामगोपाल इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि.
भागीदार अथवा 1 प्र.श.	:	
अधिक पूंजी वाले हिस्सेदार	:	ब्रज माहेश्वरी
नागरिकता	:	भारतीय
निवास स्थान	:	'नवभारत' निलयम, ई-3/22, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016

मैं आशीष श्रोती घोषित करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है.

आशीष श्रोती

दिनांक 1 मार्च 2026 प्रकाशक

महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़

उज्जैन. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए एवं विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दर्शन किये.

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा श्री धनखड़ का स्वागत एवं सत्कार किया गया.

भगवान महाकालेश्वर दर्शन पूजा अर्चना के बाद पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ में चर्चा के दौरान बताया कि भारतवर्ष में सकारात्मक बदलाव आ रहा है. और यह हमारी हजारों वर्ष पूर्व की मानसिकता है.

धान हेराफेरी : अफसरों और संचालकों पर केस दर्ज

2.79 करोड़ की धान की हेराफेरी का मामला

बालाघाट, 28 फरवरी. बालाघाट में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग से जुड़े 2.79 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बड़ी कार्रवाई की है.

अपराध क्रमांक 39/2026 दर्ज कर मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के अधिकारियों और कोसमी स्थित सचदेव राइस मिल के संचालकों को आरोपी बनाया गया है. मामला 8 दिसंबर 2023 से 20 सितंबर 2024 के बीच का बताया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार 2 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र सीमा स्थित रजेगांव इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर मिल से जुड़े दो ट्रक रोके गए. इनमें से एक ट्रक ओवरलोड पाया गया, जिस पर 12 हजार रुपये का चालान किया गया. प्राथमिक जांच में सामने आया कि ट्रक परसवाड़ा कैंप से धान लेकर कोसमी स्थित मिल जा रहे थे, लेकिन दस्तावेजों में लोडिंग का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला. चालक का भूलवश सीमा तक पहुंचने का तर्क भी संदिग्ध पाया गया.

जांच में यह भी सामने आया कि मिल की वास्तविक क्षमता 4 मीट्रिक टन प्रति घंटा थी, जबकि अनुबंध 6 मीट्रिक टन प्रति घंटा के आधार पर किया गया. आरोप है कि बिना क्षमता सत्यापन और निरीक्षण के अनुबंध स्वीकृत किया गया.

> इसके अलावा कागजों में दर्शाई गई मिलिंग के अनुपात में बिजली खपत आधी से भी कम दर्ज पाई गई, जिससे उत्पादन के आंकड़ों पर सवाल खड़े हुए हैं. ट्रक पर्ची, गेटपास, तौल पर्ची और फास्टटैग सत्यापन के बिना ही भुगतान स्वीकृत किए जाने की बात सामने आई है. पेनाल्टी और कर कटौती जैसे प्रावधानों की वसूली किए बिना 2.79 करोड़ रुपये जारी किए जाने का आरोप है. जांच एजेंसी का कहना है कि दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

प्रदेश में होली के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज

फरवरी में चार बार बदला था मौसम

भोपाल, 28 फ़रवरी. मध्य प्रदेश में इस बार फरवरी का महीना मौसम के उतार-चढ़ाव के नाम रहा. पूरे महीने में चार बार मौसम ने करवट बदली. आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जहां किसानों की चिंता बढ़ाई, वहीं अब मौसम विभाग ने होली के आसपास फिर बदलाव के संकेत दिए हैं.

2 मार्च से हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हो रहा वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है. खासतौर पर ग्वालियर-चंबल अंचल में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ लाइन सक्रिय है. इसी वजह से शुक्रवार को राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही. हालांकि बादलों के बावजूद दिन के तापमान में खास गिरावट दर्ज नहीं की गई. ओले और बारिश का दौर थमते ही प्रदेश में गर्मी ने तेजी पकड़ ली है.

> कई शहरों में दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे अप्रैल जैसी तपिश महसूस की जा रही है. सबसे ज्यादा तापमान खरगोन में 34.8 डिग्री दर्ज किया गया. भोपाल में 32.4 डिग्री, इंदौर में 31.2 डिग्री, ग्वालियर में 32.7 डिग्री और उज्जैन-जबलपुर में करीब 33 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. पचमढ़ी में दिन का तापमान 27.6 डिग्री रहा. रात के तापमान में भी खास राहत नहीं मिली. पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री दर्ज किया गया. सागर में 18.4 डिग्री और नर्मदापुरम में 18.2 डिग्री तापमान रहा.

ग्रामीण परिवहन सेवा शीघ्र शुरू होगी : उदय प्रताप सिंह

सागर, 28 फरवरी. मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य के इंदौर से ग्रामीण परिवहन सेवा शीघ्र शुरू होगी.

सिंह कल गढ़ाकोटा में तीन दिवसीय आयोजित रहस मेले को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आने वाले समय में 200 नये सांदीपनि विद्यालय शुरू किए जाएंगे, जिसमें 20 करोड़ की लागत से रहली विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में यह विद्यालय शुरू होगा. उन्होंने कहा कि परिवहन सेवा को सुगम एवं सुलभ बनाने के लिए अप्रैल माह से इंदौर से ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत होगी, जो धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में लागू होगी. मंत्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पलायन को रोकने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है, जिससे अब हमारे सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं.

विधानसभा में उठाया 400 करोड़ के फ्लाई ओवर का मुद्दा

जबलपुर. मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जबलपुर पूर्व क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने शहर एवं प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अधोसंरचना और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दों को गंभीरता से सदन में उठाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 23 तारीख को गिरे फ्लाईओवर पुल का विषय अत्यंत गंभीर है. उन्होंने उल्लेख किया कि लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित फ्लाईओवर मात्र तीन वर्ष के भीतर गिर गया, जो निर्माण गुणवत्ता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है. उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस विषय को पृथक रूप से गंभीरता से लिया जाए.

और उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए.इस मौके पर विधायक ने शिक्षा विभाग से संबंधित वित्तीय प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठाए. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में जो राशि लोक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षा विभाग को आवंटित की जाती है, वह कलेक्टर के माध्यम से पारदर्शिता के साथ वितरित होती है, किंतु द्वितीय चरण में आवंटित राशि में गंभीर अनियमितताओं की आशंका है. उन्होंने सदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि 69 करोड़ रुपये की राशि कलेक्टर द्वारा आवंटित की गई, परंतु उसके व्यय और उपयोग पर प्रश्नचिह्न है.

किसान कल्याण पर पटवारी का सवाल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 28 फरवरी जीतू पटवारी ने राज्य बजट 2026-27 को लेकर तीखा हमला बोलते हुए इसे 'किसान कल्याण' का दस्तावेज बताए जाने के दावे को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं से खेतों में व्याप्त संकट नहीं छिपाया जा सकता.

पटवारी ने कहा कि सरकार कृषि सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों की वास्तविक आय घट रही है, लागत बढ़ रही है, फसल जोखिम बढ़े हैं और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि डीज़ल, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और बिजली की कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समय पर खरीद अब भी अनिश्चित बनी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान में देरी, भंडारण की कमी और बाजार में उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान साहूकारों और बैंकों के कर्ज पर निर्भर होने को मजबूर हैं. पटवारी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 के बीच किसानों और कृषि मजदूरों की कथित आत्महत्याओं के मामलों पर पारदर्शिता की मांग की.

> उन्होंने पुनर्वास, कर्ज राहत और मानसिक स्वास्थ्य सहायता संबंधी उपायों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक करने की भी मांग की. उन्होंने उज्जैन और इंदौर संभाग में अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए मुआवजे और पुनर्वास को अपर्याप्त बताया. पटवारी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, सिंचाई विस्तार, शून्य ब्याज पर कृषि ऋण और प्रभावी आपदा राहत की मांग करते हुए कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, केवल वोट बैंक नहीं.

नितिन नवीन से मिले सीएम डॉ. मोहन और खंडेलवाल

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नई दिल्ली में भेंट की.

महिला महाप्रबंधक को भावभीनी विदाई

भोपाल, 28 फरवरी. पश्चिम मध्य रेलवे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का समापन हुआ, जब पश्चिम मध्य रेल की पहली महिला महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय अपनी अधिवार्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुई.

इस अवसर पर मुख्यालय सभागार, भोपाल में एक गरिमामयी विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें भावभीनी विदाई दी गई. समारोह में अपर महाप्रबंधक प्रमोद कुमार खत्री, प्रमुख वित्त सलाहकार मनजीत कौर एवं प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी एस.डी. पाटीदार ने बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्ति से संबंधित दस्तावेज एवं सम्मान पत्र प्रदान किए. रेल प्रशासन की ओर से उनके स्वस्थ, सुखी और समृद्ध भविष्य की कामना की गई. भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसएसई) 1987 बैच की वरिष्ठ अधिकारी शोभना बंदोपाध्याय ने 1 नवंबर 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया था. वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी रहीं. अपने लगभग 38 वर्षों के सेवाकाल में उन्होंने मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और रेलवे बोर्ड में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया.

रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय अपनी अधिवार्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुई

बजट सत्र | प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी

कांग्रेस विधायक ने निजी सदस्य विधेयक किया पेश

विशेष संवाददाता

भोपाल, 28 फरवरी. बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह ने प्रदेश में सार्वभौमिक नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा लागू करने के उद्देश्य से निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया.

इस संबंध में जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई, जिसमें पूर्व मंत्री एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे. यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 तथा मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 25(1) के तहत प्रस्तुत किया गया है. डॉ. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी को, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या आय वर्ग से संबंधित हो, प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाए. चर्चा के दौरान डॉ. सिंह ने कहा कि वर्तमान आयुष्मान भारत योजना के तहत सीमित कवरेज उपलब्ध है और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये की सीमा अपर्याप्त है. प्रस्तावित विधेयक में समाज के सभी वर्गों किसान, व्यापारी, कर्मचारी, श्रमिक एवं जनप्रतिनिधि को सार्वभौमिक कवरेज देने का प्रावधान है.

> विधेयक के अनुसार प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार मिलेगा, जबकि किडनी और लीवर प्रत्यारोपण, कैंसर तथा अन्य जटिल सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए यह सीमा 25 लाख रुपये तक होगी. डॉ. सिंह ने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का उपचार उपलब्ध है. किंतु पात्रता संबंधी शर्तों जैसे बीपीएल सूची में नाम, राशन कार्ड या विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन के कारण केवल लगभग 52 प्रतिशत परिवारों को ही इसका लाभ मिल पाता है.

पेज एक का शेष

सरकार और संगठन में कुछ बड़ा होने के संकेत

सिंह के साथ मुलाकात की. इन मुलाकातों का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में दिखने की संभावना जताई जा रही है. मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शनिवार को कूनो में बोतस्वाना से आए चीतों को खुले बाड़े में छोड़ने का काम केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने अकेले किया. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव दिल्ली में व्यस्तता के कारण शामिल नहीं हो सके. इधर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री शाह से विजयवर्गीय की मुलाकात को सामान्य राजनीतिक मुलाकात नहीं माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि संभवत: केंद्रीय नेतृत्व विजयवर्गीय के हाल के बयानों से नाराज है. विजयवर्गीय ने पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में भोपाल, इंदौर के मास्टर प्लान नहीं आने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था, वहीं सत्रावसान के समय जब मुख्यमंत्री डॉ. यादव सदन में नहीं थे, तब भी विजयवर्गीय ने विधानसभा सचिवालय को सरकार के सचिवालय से बेहतर करार देकर एक तरह से सीएम और सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला ही किया था. बताया जा रहा है कि ये मामला तेजी से वायरल हुआ और मामले की शिकायत दिल्ली तक की गई. मामला संज्ञान में आने के बाद विजयवर्गीय को शुक्रवार देर रात ही दिल्ली तलब किया गया, उसके बाद आनन-फानन में वे रात को ही दिल्ली रवाना हो गए. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के एक और कद्दावर मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी शाह से अलग से मुलाकात की. इधर सीएम की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के कामकाज के साथ ही संगठन के कामकाज की जानकारी शाह के साथ साझा की. उनकी इस मुलाकात को आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में बदलाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद अब इस संबंध में भाजपा हाईकमान से कोई संकेत मिल सकते हैं. यदि ऐसा हुआ तो सीएम और सरकार के लिए समस्या खड़ी करने वालों के साथ ही नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बाहर का दरवाजा दिखाया जा सकता है.